

घाटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 14 - शुक्रवार 14 - नवम्बर 2025, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये, www.ghatati-ghatana.com, RNI Reg. No. - CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन क्र. 13/Surguja DN/ 2023-2025

हर आतंकी घटना के बाद कांग्रेस करती है घटिया राजनीति : प्रह्लाद जोशी

बंगलुरु, 13 नवम्बर 2025। दिल्ली विस्फोट के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी कोई विस्फोट या आतंकवादी हमला होता है तो कांग्रेस बेहद निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आती है। अब दिल्ली विस्फोट में भी वह यही कर रही है। गुरुवार को संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जोशी ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से देश हिल गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं और विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। मानो वे आतंकवादियों को पनाह दे रहे हों। जोशी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट और बिहार चुनाव के बीच क्या संबंध है? कांग्रेस नेताओं को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए। जोशी ने जमीर अहमद पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देने और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली निम्नस्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंत्री जोशी ने दिल्ली कार विस्फोट घटना की कड़ी निंदा की है, जिसमें 12 निर्दोष लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, फिर भी उनका ऐसा बोलना वास्तव में शर्मनाक है, जैसे कि उन्हें जीवन का मूल्य ही नहीं पता। उन्होंने कहा कि दिल्ली विस्फोट-आतंकवादी घटना की जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेता जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे हर मामले में पाकिस्तान जैसे बयान दे रहे हैं, चाहे वह बंगलुरु कैफ़े विस्फोट हो या पहलगाम आतंकी हमला। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, तो आतंकवादियों को परास्त करने के लिए निष्पक्ष समर्थन दिखाना चाहिए और एकजुटता की ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं शांति भंग करने वाले कुछ ही लोग : उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं, बल्कि शांति भंग करने वाले कुछ लोग ही हैं। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि जब जम्मू-कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही विचारधारा से देखते हैं और सोचते हैं कि उनमें से हर एक आतंकवादी है, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में कथित आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि इस क्षेत्र में शांति और भाईचारे को नष्ट करने वाले कुछ ही लोग हैं और हर कश्मीरी को आतंकवाद से जुड़ा बताना उचित नहीं है। कोई भी धर्म इतनी क्रूरता से निर्दोष लोगों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। जांच जारी रहेगी, लेकिन कुछ ही लोग हैं, जिन्होंने हमेशा शांति और भाईचारे को नष्ट किया है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने का आह्वान किया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि निर्दोष लोग इससे दूर रहें। उन्होंने कहा कि क्या हमने इससे पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को नहीं देखा... कौन कहता है कि पढ़े-लिखे लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते हैं।

मोबाइल का वॉटरप्रूफ वाला दावा फेल, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

संतकबीरनगर, 13 नवम्बर 2025। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक महंगे 'वॉटर प्रूफ' मोबाइल के पानी की हल्की बूंदों से खराब हो जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्माता कंपनी और विक्रेता को मोबाइल की पूरी कीमत 10% ब्याज के साथ लौटाने और क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सैमसंग कंपनी को मोबाइल की कीमत सहित ब्याज वापस करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई संतकबीरनगर जिले के उरुका कला निवासी शक्ति विकास पांडेय की शिकायत पर हुई है। उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। पांडेय के मुताबिक, कंपनी द्वारा वॉटरप्रूफ बताकर बेचा गया मोबाइल हल्की बारिश की बूंदों से खराब हो गया था। उनकी शिकायत पर न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दरअसल, खलीलाबाद के उरुका कला निवासी शक्ति विकास पांडेय ने 28 दिसंबर 2022 को खलीलाबाद स्थित अग्रवाल टेलीकॉम से 1,57,998 में सैमसंग का फोल्ड फोन मोबाइल खरीदा था।

दिल्ली ब्लास्ट : आतंकी लेना चाहते थे बाबरी का बदला देशभर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी, दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था...

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर, यानी बाबरी मस्जिद दहलाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजाइर, इकोस्पोर्ट और आई20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं। जांच एजेंसियों को अब तक कार कारों बरामद हो चुकी हैं। 10 नवंबर जिस आई20 कार में धमाका हुआ था, वह इसी सीरियल रिजर्वेज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।

दिल्ली ब्लास्ट में खुलासे...

जनवरी में लाल किले की रेकी की थी...

दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डेटा से पता चला कि फरीदाबाद की अल फलाह युनिवर्सिटी से गिरफ्तार अरिस्टो प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉ. उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा-और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो तब नाकाम हो गई।

दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का प्लान था...

नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतरराष्ट्रीय मोड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉ. निसार फारार है। वह डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अलफलाह में पढ़ा रहा था। जम्मू-कश्मीर सरकार ने डॉ. निसार को बर्खास्त कर दिया है।

दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे...

दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था। जिन डॉक्टरों के दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया, उनके मंसूबे और खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे। 26/11 हमले की तरह साजिश अंजाम तक पहुंचने वाली थी।



खाद की बोरी बता विस्फोटक जुटा रहा था गनी

फरीदाबाद की अल फलाह युनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉ. मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर विस्फोटक कटार कर के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था, तब पड़ोसियों ने उससे पूछा था कि इसमें क्या है? जबवा में मुजम्मिल ने कहा था कि ये खाद के कंटे हैं। इन्हें कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने फुटेज जवाब कर लिए हैं।

अल फलाह विश्वविद्यालय की भूमिका सदिध

अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद जिले के धौल इलाके में स्थित है और इसके परिसर में एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी संचालित होता है। अधिकारियों ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ, उससे चला रहा नबी इसी विश्वविद्यालय में अरिस्टो प्रोफेसर था। धमाके के बाद तीन डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनका संबंध इसी संस्थान से बताया जा रहा है।

बिहार में 38 जिलों के 46 केंद्रों पर मतगणना आज

पटना, 13 नवम्बर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के उपरांत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती कराने को लेकर तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। बिहार में बीते 6 और 11 नवम्बर को संपन्न 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 67.13 प्रतिशत रिक्त रिक्त मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए हैं। कुल 7.45 करोड़ मतदाता 2,616 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला कर चुके हैं। इंतजार अब परिणाम का है। शुक्रवार को सुबह आठ बजे सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके उपरांत 8.30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतगणना की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतगणना केंद्र की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा। आयोग ने सभी निर्वाची अधिकारियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, माइक्रो आब्जर्वर एवं सहायकों को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी



मतगणना कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पटना जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें वाले जिले में वोटों की गिनती के लिए सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया है। पटना के एएन कॉलेज में 14 विधानसभा सीटों की गिनती की जाएगी। एक से ज्यादा काउंटिंग सेंटरों में सहरसा, भागलपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, सीवान और पूर्णिया जिले के नाम हैं। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन सभी सीटों के लिए टीचर ट्रेनिंग नॉलेज, मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर मधुबन, सुपौली, नरकटिया, चिरैया, हाका और रक्सौल की सीटों की गिनती की जाएगी। इसके

पंजाब में विदेशी हैंडलरों से जुड़े 10 मुख्य सहयोगी गिरफ्तार, ग्रेनेड हमले की साजिश बेनकाब

चंडीगढ़, 13 नवम्बर 2025। लुधियाना पुलिस आयुक्तालय ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े 10 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआई समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपित मलेशिया स्थित तीन सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे, ताकि हैंड ग्रेनेड की प्राप्ति और आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित किया जा सके। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है, जो सभी मुक्तपत्र साहिब के निवासी हैं। अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिड़्डी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुख बराड़, सुखविंदर सिंह, कनवीर सिंह उर्फ विक्की और सजान कुमार उर्फ संजू को कूरियर और सहयोगी की भूमिका निभाने के आरोप में विभिन्न जेलों से प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया है।

अमित शाह ने गुजरात में किया मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मणसा में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल (एमआरसीएसएसएस) और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर शाह ने हाल ही में दिल्ली में हुए कार विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि इस हमले के दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने आतंकवाद के

रेगिस्तानी क्षेत्र के 'अखंड प्रहार' अभ्यास में थल सेना और वायु सेना ने दिखाया सहज तालमेल

जयपुर, 13 नवम्बर 2025। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने तीनों सेनाओं के अभ्यास 'त्रिशूल' के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र में 'अखंड प्रहार' का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन्-चीफ लोफ्टिनट जनरल धीरज सेठ ने अभ्यास के दौरान कोणाकं कोर की युद्धक तैयारियों की समीक्षा की। डिफेंस पीआरओ लोफ्टिनट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस अभ्यास ने रुद्र ब्रिगेड द्वारा जमीनी अभियानों, विशेष हेलीबोर्न अभियानों और आर्मी एविएशन द्वारा समन्वित हमलावर हेलीकॉप्टर मिशन सहित मशीनीकृत और पैदल सेना युद्धाभ्यासों से लेकर सभी आर्म्स और सर्विसेस के एकीकृत उपयोग के माध्यम से कोणाकं कोर की पूर्ण-स्पेक्ट्रम युद्ध तत्परता को प्रमाणित किया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय थल सेना और



भारतीय वायु सेना के बीच सहज तालमेल देखा गया और इसमें पैदल सेनाओं के फाइटर ग्राउंड अटैक मिशन भी शामिल थे। यह अभ्यास भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी की स्वदेशी तकनीकों के वास्तविक युद्धक परिस्थितियों में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मंच भी रहा। स्वदेशी ड्रोन, मानवरोहित प्रणालियां, ड्रोन-रोधी प्रणालियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गिड का उपयोग, रक्षा में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

पुणे में 25 गाड़ियां टकराई, 9 लोगों की मौत

ट्रकों के बीच दबी कार में आग लगी, कटेनर भी जला, ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा

पुणे, 13 नवम्बर 2025। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक और कटेनर के बीच में फंसी एक कार में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई 25 लोग घायल हो गए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मरने वालों में 5 कार सवार थे। ट्रक के ड्राइवरों की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, हादसा पुणे-नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ। ट्रकर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कटेनरों के बीच दब गई और आग लगने के कुछ सेकेंड में ही लपटों में धिर गई। मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद करीब एक घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है।



से पुणे की ओर आ रहे दोनों ट्रकों के बीच कार फंस गई थी। इससे दोनों ट्रकों और कार में आग लग गई। हादसे के कारण नवले ब्रिज पर लंबा जाम लग गया है। पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर अभी भी ट्रक में फंसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वह आगे जा रही कार से टकराया जिससे वह कटेनर से जा भिड़ी और

सीएम फडणवीस ने मदद का ऐलान किया

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया। सांसद सुप्रिया सुले ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।

पुणे-बंगलोर नेशनल हाईवे पर नवले ब्रिज पर हुआ हादसा

इस हादसे के बाद पुणे-बंगलूर हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। दो कटेनरों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। नवले ब्रिज पर हुए इस हादसे के बाद काफी हंगामा हुआ। शुरुआत में बताया गया था कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है, बाद में यह संख्या बढ़कर अब सात हो गई है।

टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई ने हासिल की ऐतिहासिक रफ्तार : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तपेदिक (टीबी) नियंत्रण में मिली ऐतिहासिक सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि भारत में टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है और यह गिरावट वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी तेज है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को एक्स पर लिखा, 'टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत ने 2015 से अब तक टीबी की घटनाओं में सराहनीय कमी दर्ज की है, जो वैश्विक औसत दर से लगभग दोगुनी है। यह दुनिया में दर्ज हुई सबसे तेज गिरावटों में से एक है। उतना ही उत्साहजनक है उपचार कवरेज का बढ़ना, 'मिसिंग केस' की कमी और उपचार सफलता में निरंतर वृद्धि। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सफलता में योगदान दिया है। हम एक स्वस्थ और फिट भारत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के नए मामलों (टीबी इंडेक्स) में 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है- 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों थे, जो 2024 में घटकर 187 रह गए हैं। यह दर वैश्विक औसत गिरावट



(12 प्रतिशत) की तुलना में लगभग दो गुना है। भारत ने टीबी मृत्यु दर को भी उल्लेखनीय रूप से घटाया है। वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 मौतें होती थीं, जो 2024 में घटकर 21 रह गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार कवरेज 92 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो अन्य उच्च-भार वाले देशों और वैश्विक औसत से अधिक है। साथ ही उपचार सफलता दर 90 प्रतिशत रही है, जबकि वैश्विक दर 88 प्रतिशत है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्यकर्मियों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, निरचय मित्रों और टीबी उन्मूलन मिशन से जुड़े सभी नागरिकों को देते हुए कहा कि यह सफलता जनभागीदारी और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का प्रमाण है।

संपादकीय



शीघ्र लागू की जाएं चारों श्रम संहिताएं

संतुलित विकास का ढांचा प्रदान करने में सक्षम होंगी

भारत के कार्यबल को ऐसे औपचारिक रोजगार में तेजी से जगह मिलनी चाहिए, जहाँ उचित वेतन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिले, जिससे विकास के लाभ से सभी को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो। पुराने श्रम नियमों के बने रहने से गुणवत्तापूर्ण रोजगार देने की उद्यमों की क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित हुई। इसी के आलोक में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम सुधारों की जो कल्पना की, वह काफी समय से लंबित थी। इन्हें 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा चार श्रम संहिताओं के रूप में पारित किया गया। ये संहिताएँ देश के श्रम परिदृश्य को आधुनिक बनाने और संरचनात्मक अस्तुतलों को दूर करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। दशकों पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाते हुए चार नई श्रम संहिताओं के निर्माण का उद्देश्य न केवल कानूनों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करना है, बल्कि काम को अधिक निष्पक्ष सुरक्षित और उत्पादक बनाना है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है कि प्रत्येक श्रमिक को श्रम की गरिमा का सम्मान करने वाला न्यूनतम वेतन मिले। पहले न्यूनतम वेतन केवल निर्धारित व्यवसायों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे सभी क्षेत्रों और संगठित और असंगठित के समस्त श्रमिकों पर लागू कर दिया गया है। यह न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिकरण श्रमिकों को कानूनी रूप से बुनियादी वेतन का अधिकार देता है। इसके साथ ही पहली बार एक राष्ट्रीय आधार वेतन (फ्लोर वेज) की व्यवस्था की गई है, जिसे केंद्र सरकार जीवन स्तर और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय करेगी। कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं तय कर सकता। इससे राज्यों के बीच वेतन असमानता भी घटेगी और देशभर के श्रमिकों को समान अवसर मिलेगा। संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि वेतन की समीक्षा नियमित रूप से हो, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप श्रमिकों की आय प्रासंगिक बनी रहे। इस संहिता के तहत विवादों में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार नियोक्ता पर होगा, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 स्वतंत्र भारत में जन कल्याण के सबसे समावेशी विस्तारों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और प्रसूति प्रसूति अधिनियम सहित नौ प्रमुख कानूनों को मिला कर यह एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है, जो पारंपरिक और नए, दोनों प्रकार के कार्यों को कवर करती है। पहली बार गिंग श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय कार्यबल का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक श्रमिक को पंजीकृत किया जाएगा, उसे एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व सहायता जैसे लाभ का सीधा वितरण संभव हो सकेगा।

मधुमेह को दवा से ही नहीं, संतुलित जीवन से परास्त करें

दुनिया में बढ़ती मधुमेह की भयावहता इसलिये चिन्ताजनक है कि हर तीसरा शहरी वयस्क डायबिटीज से जुड़ा रहा है। यह बीमारी अनेक अन्य बीमारियों को भी बढ़ाने का बड़ा कारण है। मधुमेह के बढ़ने के कारणों में मुख्यतः खानपान में अनियमितता और शारीरिक निष्क्रियता सबसे बड़ी वजह है। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज कर दुनिया को मधुमेह से राहत देने का मार्ग दिखाया। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1991 में इसकी शुरुआत की थी। इस वर्ष का थीम है मधुमेह और समग्र कल्याण। यह थीम इस तथ्य पर केंद्रित है कि मधुमेह का उपचार केवल दवाइयों से नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली से संभव है। मधुमेह आज एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। बदलती जीवनशैली, अनियमित भोजन, तनाव, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता इसके प्रमुख कारण हैं। यह बीमारी चुपचाप शरीर को भीतर से खोखला करती है और हृदय, गुर्दे, आंखों और नसों पर गहरा असर डालती है। मधुमेह को नियंत्रित करना केवल चिकित्सा का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। इसके लिए सबसे पहले जीवन में संतुलन एवं सात्विक जीवनशैली की आवश्यकता होती है यानी संतुलित आहार, संतुलित नींद, संतुलित विचार और संतुलित आचरण। जीवन का यह संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। जब हम अपने जीवन को एक अनुशासन में ढालते हैं, तो रोग अपने आप दूर भागते हैं। मधुमेह आज केवल रोग नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है।

मधुमेह का प्रबंधन केवल दवा और आहार तक ही सीमित नहीं है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, तनाव प्रबंधन, जीवनशैली शिक्षा और



ललित राणा
पटवर्जा, दिल्ली-

सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल है। इसका लक्ष्य रोगी को मधुमेह की चुनौतियों का सामना करते हुए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। समग्र देखभाल, शीघ्र हस्तक्षेप और सहायक वातावरण को बे जवा देकर, मधुमेह रोग के बजाय व्यक्ति के उपचार के महत्व पर जोर देना मधुमेह दिवस का उद्देश्य है। यह दिवस मधुमेह से पीड़ित लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का अभियान डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और समुदायों से आग्रह करता है कि वे केवल रक्त शर्करा के स्तर से आगे बढ़ें और रोग के संपूर्ण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। डायबिटीज जैसी घातक एवं असाध्य बीमारी को नियंत्रित करने के लिये अफवाहों से बचना जरूरी है, इसके लिये बड़ा दिल नहीं, समझदार दिल होना चाहिए। मर्यादित आहार ही, इस बीमारी को रोकने का एक सस्ता और असरदार उपाय हो सकता है। डायबिटीज (मधुमेह) की समस्या भारत समेत पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज



पहले अमूमन अंधेड़ उम्र के लोगों में होती थी, अब यह बच्चों एवं युवकों को भी शिकंजे में ले रही है। भारत में करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। वहीं विश्व में 44 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। भारत में डायबिटीज की प्रचलित दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि प्री डायबिटीज के मामलों की दर 15.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है, यानी देश का हर 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है। एक अनुमान के अनुसार 85 करोड़ लोग दुनिया भर में डायबिटीज के मरीज 2050 तक हो जाएंगे। मधुमेह से बचने और इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नियमित शारीरिक गतिविधि। सुबह-सुबह की सैर, हल्का व्यायाम, दौड़ना या साइकिल चलाना न केवल शरीर को सक्रिय रखता है बल्कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी संतुलित करता है। इसके साथ ही योग और ध्यान का अभ्यास मधुमेह के नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी माना गया है। योग केवल शरीर को लचीला नहीं बनाता बल्कि मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे योग अभ्यास इंसुलिन के स्त्राव को संतुलित करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। ध्यान से मन की अस्थिरता और चंचलता कम होती है, जिससे तनाव नियंत्रित रहता है। तनाव और अवसाद मधुमेह के खिप्पे हुए शत्रु हैं। जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाते हैं। इसलिए मन को शांत और

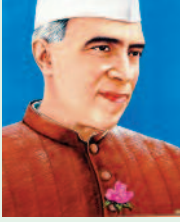
ले लिए इन मानसिक विषाणुओं को दूर रखना उतना ही आवश्यक है जितना दवा लेना। अपने मन को हल्का और हृदय को प्रसन्न रखने की कला सीखनी होगी। धार्मिक प्रवृत्तियाँ, सत्संग, संगीत, साहित्य, प्रकृति के निकट समय बिताना, परिवार के साथ हंसी-मजाक करना-ये सब जीवन को संतुलन और आनंद से भर देते हैं। मधुमेह के रोगियों को नियमित रूप से अपने शूगर स्तर की जांच करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। दवा के साथ-साथ आत्म-निगरानी और जीवनशैली में निरंतर सुधार ही स्थायी स्वास्थ्य का आधार है। छोटी-छोटी बातों में सावधानी बें बीमारियों से रक्षा करती है। शरीर को सक्रिय रखना, मन को शांत रखना और भोजन को संयमित रखना-ये तीन सूत्र मधुमेह नियंत्रण के त्रिवेद हैं। इस वर्ष के विश्व मधुमेह दिवस का संदेश यही है कि केवल दवा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलनी होगी। मधुमेह को नियंत्रण में रखने का सबसे कारगर उपाय है-संतुलित जीवन। जब मन, शरीर और आत्मा का समन्वय होता है तो स्वास्थ्य अपने आप खिल उठता है। इस 14 नवम्बर को हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जीवनशैली को अनुशासित, सकारात्मक और स्वास्थ्य-केंद्रित बनाएंगे। नियमित योग और ध्यान करेंगे, भोजन में संयम रखेंगे, तनाव को दूर करेंगे और अपने शरीर को प्रेम से समझेंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मधुमेह जैसी बीमारी हमें चपभौत करने के लिए नहीं आई, बल्कि हमें सजग, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने का संदेश देने के लिए आई है। अगर हम यह संदेश समझ जाएं तो मधुमेह भी जीवन के संतुलन की शिक्षक बन जाती है।

जवाहर लाल नेहरू के 136 वीं जन्म दिवस पर विशेष बच्चों के चाचा-जवाहर लाल नेहरू



लाल बिहारी लाल

बच्चों हर देश का भविष्य और उसकी तस्वीर होते हैं। बच्चे ही किसी देश के आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं। लेकिन



27 मई, 1964 को उनका निधन हो गया।

बच्चों के चाचा नेहरू

एक दिन तीन मूर्ति भवन के बगीचे में लगे पेड़-पौधों के बीच से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते पर नेहरू जी टहल रहे थे। उनका ध्यान पौधों पर था, तभी पौधों के बीच से उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। नेहरूजी ने आसपास देखा तो उन्हें पेड़ों के बीच एक-दो माह का बच्चा दिखाई दिया जो रो रहा था। नेहरूजी ने उसकी मां को इधर-उधर ढूँढ़ा पर वह नहीं मिली। चाचा ने सोचा शायद वह बगीचे में ही कहीं माली के साथ काम कर रही होगी। नेहरूजी यह सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाने का मन बना लिया। बच्चे को गोद में उठाकर हसल खिलाने लगे और वह तब तक उसके साथ रहे जब तक उसकी मां वहाँ नहीं आ गईं। उस बच्चे को देश के प्रधानमंत्री के हाथ में देखकर उसकी मां को यकीन ही नहीं हुआ।

दूसरा वाक्या जुड़ा है तमिलनाडु से, एक बार जब पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौर पर गए तब जिस से क से वे गुजर रहे थे वहाँ लोग साइकलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहाँ समझ आया वहाँ खड़े होकर नेहरू जी को निहारने लगा। इस भी भरे इलाके में नेहरूजी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खिले डगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह-तरह के रंग-बिरंगी गुब्बारे मानो पंडितजी को देखने के लिए खोल रहे हों। जैसे वे कह रहे हों हम तुम्हारा तमिलनाडु में स्वागत करते हैं। नेहरूजी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुँची तो गाड़ी से उतरकर वे गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का-बक्का-सा रह गया। नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहाँ उपस्थित सारे बच्चों को वे गुब्बारे बंटवा दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे-जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुँचे बच्चों ने चाचा नेहरू-चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहाँ का वातावरण उल्लासित कर दिया। तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भारत के भारत में इस तरह के महान मानव का जन्म बहुत कम ही हो रहा है जो देश के युवाओं एवं बच्चों की सोंच रखता है और इसके चहुमुखी विकास की बात करता है।



प्रो.शामलाल कौशल
रोहतक, हरियाणा

आज के बच्चे कल का भविष्य है। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ भोला भाला बच्चों का चेहरा किसे पसंद नहीं होगा? बच्चों के साथ समय बिताना, खेल कर और छोटे बच्चों को उत्साह सब तनाव दूर हो जाता है और मन में शांति मिलती है। इसी बात को लेकर हमारे देश में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस या फिर चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। इस दिन बाल दिवस मनाने का मुख्य कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होना भी है। नेहरू जी के जन्मदिन को ही... बाल दिवस... के तौर पर मनाया जाता है। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी को देश से संबंधित कितनी कठिनाइयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। गरीब जनता का कल्याण, देश का विकास, विदेशी नीति, देश की सुरक्षा, कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के साथ संबंध, देश विभाजन के फल स्वरूप उत्पन्न समस्याएँ आदि ने नेहरू जी के दिमाग के ऊपर दबाव डाला होगा। इस दबाव या तनाव से बचने के लिए उन्होंने अपने जन्मदिन को... बाल दिवस... के तौर पर मनाने का फैसला किया। उन्हें बच्चों के साथ अधिकतम समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों में उन्हें देश का भविष्य नजर आता था। बच्चे भी नेहरू जी को लाड़ प्यार से... चाचा नेहरू... कह कर पुकारते थे! वह बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी खेलकूद

वो लाल गुलाब

तथा भाग दौड़ की सुविधा तथा अच्छी सोच देना चाहते थे। सबसे पहले 1954 में 14 नवंबर वाले दिन... बाल दिवस... मनाया गया। उसके बाद हर साल हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। जब नेहरू जी जीवित थे तब जगह-जगह... चिल्ड्रेन पार्क... बनवाए गए। खेलने के लिए उन पार्कों में बहुत सारी सुविधाएँ रखी गईं। शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। गरीब बच्चों की हर प्रकार से सहायता की जाती थी। आजकल भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि स्वरूप देश में हर साल 14 नवंबर को... बाल दिवस... अथवा चिल्ड्रेन डे... मनाया जाता है। नेहरू जी बच्चों की तुलना लाल गुलाब से करते थे। उनका कहना था जिस तरह सब फूलों में लाल गुलाब ही सबसे ज्यादा सुंदर और मन खुश करने वाला होता है इस तरह हम मनुष्यों में भी बच्चे गुलाब की तरह सुंदर और खुश करने वाले होते हैं। नेहरू जी बच्चों के साथ समय बिताना खुश होते थे और उनका तनाव तथा दिमाग का बोझ छुमंतर हो जाता था। पंडित नेहरू हमेशा चूड़ीदार पनामा तथा सफेद अचकन पहनते थे और अचकन की जेब के ऊपर लाल गुलाब लगाते थे। इस लाल गुलाब के कारण उन्हें ऐसा लगता था जैसे बच्चे उनके साथ हो और वह प्रसन्नचित रहने की कोशिश करते थे। उनका कहना था कि मासूम बच्चे की हँसे सच्चे होते हैं। अगर वह संस्कारी होंगे, बहादुर होंगे, शिक्षित तथा प्रशिक्षित होंगे, कोमल हृदय वाले होंगे तब बड़े होने पर उनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह किसी और राजनेता ने बच्चों के साथ उतना प्रेम नहीं दिखाया, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचा। तभी तो आज के बच्चे पंडित नेहरू के सपनों के बच्चों की तरह नहीं हैं। आज के बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है। उनका



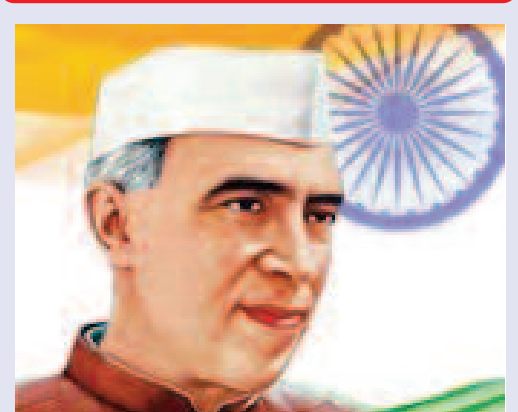
बस्ता उनके अपने वजन से भी ज्यादा भारी है। पढ़ाई का पाठ्यक्रम ऐसा है जिसके अनुसार उनका सारा समय स्कूल के बाद होमवर्क करने तथा ट्यूशन पर जाने में ही बीत जाता है। आज के बच्चे अपना समय मोबाइल पर लगाकर अपनी आँखें खराब करते हैं और उन्हें समय से पहले बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं जिससे वह जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मोबाइल पर ही वह इंडोर गेम खेलते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, भाग दौड़ करना, गुब्बी डंडा खेलने, कचे खेलना आदि आउटडोर गेम के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं। उनका ज्ञान किताबी ज्ञान तक ही सीमित है। उन्हें देश के स्वतंत्रता सेनानी, आध्यात्मिक पुरुषों, अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धा में पदक लाने वालों आदि का बिल्कूल पता नहीं। अधिकांश बच्चे अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं जानते। पढ़ाई तथा मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देने के कारण तबाल कुपोषण के कारण बहुत सारे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। जो बच्चों की आजकल शौचनीय स्थिति है वैसी पंडित नेहरू ने कभी कल्पना नहीं की थी। यूँ औपचारिकता के तौर पर हमारे देश में हर साल पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि स्वरूप... बाल दिवस... तो जरूर मनाया जाता है परंतु बाल दिवस की भावना तथा उद्देश्य कहीं नजर नहीं आते। अधिकांश बच्चों के चेहरे उदास, तनावग्रस्त, गुस्सेवाले तथा निराश दिखाई देते हैं। अधिकांश बच्चे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें हिंदी की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। यह भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का अपमान है। बाल दिवस तो साल में एक बार मनाया जाता है परंतु हमें अपने बच्चों को संस्कारी, आज्ञाकारी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, माँ-बाप तथा बड़ों की इज्जत करने वाले, संयमी, कठिन परिश्रम करने वाले, देश भक्तों के बारे में जानने वाले, देश की संस्कृति को जानने वाले तथा ईमानदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी ही सच्चे अर्थों में... बाल दिवस... मनाया सार्थक होगा।

कविता



मोनिका डगा आनंद,
चेन्नई, तमिलनाडु

बाल दिवस विशेष



बाल दिवस का होगा महासत्त्व विद्यालय के प्रांगण में, झुमेगे हम सारे मिलकर जान मंदिर के प्यारे आंगन में, चाचा नेहरू जी ने शुरू किया हमारे लिए ये दिन प्यारा, भूल जाते हम इस दिन पढ़ाई-लिखाई का प्रसंग सारा। बच्चे होते हैं मन के कोमल गुलाबों सा उनका रंग रूप, बोली उनकी मधु सी मीठी आत्मा में बसता ईश्वर अनुप, मत तुम उनपर इतना बोझा डालो करना जाएंगे वो सूख, चहल-पहल व उछल-कूद की होती उनमें ज्यादा भूख। बंद कर सारी काँपी किताबें बच्चे तो भई मौजों मनाएँ, नहीं सुनेंगे आज किसी की वो खुशियों की धुन गुनगुनाएँ, खेल कूद व मनोरंजन संग थोड़ा जोर-शोर से होगा हंगामा, गुरुजन संग खेलेंगे आँख-मिचौली होगा थोड़ा ज्यादा ड्रामा। हँसो-हँसाओं और नाचो-गाओ एक दिन सब बच्चे बन जाओ, बचपन में जाकर फिर से बच्चों संग यादों को जोकर आओ, जान मंदिर में आज गुंजेगी चहल-पहल आनंद किलकारी, महक उठेगी फिर से सुन्दर रंग-बिरंगी ये प्यारी सी फुलवारी। बच्चों को रहने दो बच्चे वो अपने आप समय से संभल जाएँगे, खुशी-खुशी वो ज्यादा बेहतर आज से आने वाला कल बनाएँगे, बच्चों पर निर्भर करता है किसी भी राष्ट्र का भविष्य दिव्य, रमने दो उनमें निडरता, आत्मविश्वास व साहस के कण नित्य।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा। -सम्पादक

नई सड़क की गुणवत्ता पर सोशल मीडिया में फूटा जनाक्रोश

इंजीनियरों व नगर निगम पर उठे सवाल, राष्ट्रपति के आगमन से जोड़कर भी कर रहे लोग तीखी टिप्पणी

- गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण को लेकर आक्रोश, लोगों ने कहा भ्रष्टाचार की हद हो गई...
- अंबिकापुर शहर में हो रहा है सड़क निर्माण, निर्माण होते ही उखड़ रही है सड़क...
- एक दिन में ही सड़क की हालत हो रही है पहले की तरह, लोगों ने सड़क की हालत साझा की सोशल मीडिया पर...



सामग्री पर उठे सवाल

कई यूजर ने टिप्पणी की कि सड़क में डामर की बजाय घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। एक व्यक्ति ने लिखा 'डामर नहीं है, मोबिल है मिट्टी में मिला।' लोगों का कहना है कि सड़क पर बिछाई गई परत बेहद कमजोर है और जल्द ही उखड़ने की स्थिति में आ सकती है।

राष्ट्रपति के आगमन से जोड़कर उठार सवाल

कुछ टिप्पणियों में आगामी 20 नवंबर को राष्ट्रपति के संभावित आगमन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। लोगों का कहना है कि केवल दिखावे के लिए जल्दबाजी में सड़कें बनाई जा रही हैं। एक यूजर ने लिखा- 'लीपा-पोती चल रहा है, राष्ट्रपति आ रही है उसके लिए।' दूसरे ने आरोप लगाया कि सिर्फ राष्ट्रपति के रूट वाली सड़कें सुधारी जा रही हैं, जबकि बाकी शहर की सड़कें जस की तस खराब पड़ी हैं।

एक यूजर ने लिखा...

'सब मिलाकर 40% पैसा कमीशन में चला जाता है ठेकेदार वेईमान नहीं पूरा विभाग का कमीशन बंधा होता है।' कुछ नागरिकों ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्यों की जांच आरटीआई के माध्यम से कराई जानी चाहिए और इंजीनियरों से जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

जन्त का फूट गुस्ता... एक यूजर ने लिखा

तबे समय से शहर सड़क विहीन रहा, अब दर से जागे हैं, वह भी सिर्फ बजरी धिक्कर ना डामर दिख रहा, ना बुलडोजर। ऐसे में जन्ता गाली न दे तो क्या करे? कई लोगों ने यह भी शिकायत की कि सड़क निर्माण के बाद घूल उड़ रही है और सड़कें केवल 2-3 वर्ष के लिए ही बनाई जा रही हैं।

जांव की मांग तेज...

लगातार बढ़ रहे जन आक्रोश को देखते हुए लोग नगर निगम और संबंधित विभाग से निर्माण की गुणवत्ता की जांच, जिम्मेदार इंजीनियरों की पहचान और कार्य में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

इमल्शन का कम उपयोग नई सड़कों के उखड़ने का कारण, आरोप

अंबिकापुर शहर में नई बन रही सड़कें बनते ही उखड़ जा रही हैं यह आरोप भी लग रहे हैं और ऐसा देखने से भी समझ में आ रहा है, नई सड़क बनते ही क्यों उखड़ जा रही है इसके पीछे की वजह भी शहर के लोगों द्वारा बताई जा रही है, कुछ जानकार लोगों का कहना है सड़क निर्माण में सबसे बड़ी खामी जो है वह है इमल्शन का निर्माण के दौरान कम उपयोग, इमल्शन ही जानकारों के अनुसार सड़क में बिछाए जाने वाले पदार्थों को आपस में जोड़ने का और खासकर निचले हिस्से से सड़क के काम करता है, निर्माण के दौरान इम्यूल्शन का उपयोग नहीं किया जा रहा है अच्छी तरह इसलिए सड़क बनते ही उखड़ जा रही है ऐसा जानकारों का कहना है, जानकारों के अनुसार यह सबसे बड़ी चोरी है जो भ्रष्टाचार है स्पष्ट जिसके कारण सड़क एक दिन में ही उखड़ जा रही है।

बिना साफ-सफाई किए ही डामरीकरण सड़क उखड़ने की एक वजह, जानकार

जानकारों के अनुसार सड़क बनते ही उखड़ जाने की एक वजह यह भी है कि सड़क जिन जगहों या पुराने मार्गों पर बनाई जा रही है उन सड़कों जगहों की सफाई नहीं की जा रही है, यदि सड़क में डामरीकरण कार्य के पूर्व बेहतर साफ सफाई की जाए सड़क के निचले हिस्से से डामर युक्त सड़क निर्माण सामग्री चिपकेगी और सड़क मजबूत होगी, जानकारों के अनुसार यह चोरी भी पैसे बचाने की जाती है जिससे निर्माण एजेंसी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है।

रही हैं जिसमें गुणवत्ता जैसा कोई मामला शामिल नहीं है और इस तरह के लगे रहे आरोप सही है। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कुछ ने इसके लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया है वहीं कुछ ने नेताओं और अधिकारियों को दोषी बताया है वहीं ने इन सभी के साथ विपक्ष को भी जिम्मेदार बताया है और इसके लिए उनके मौन को कारण बताया है, अंबिकापुर शहर जो सरगुजा जिले का संपातीय मुख्यालय है कि सड़कें बेहद खराब हैं, सड़कों की हालत बरसात के समय तो ऐसी थी जैसे गहरे खेतों से होकर आना जाना कर रहे हैं लोग, लोगों ने साथ ही आलोचकों को जवाब देकर सड़क निर्माण कार्य आरंभ हुआ लेकिन जैसी सड़कें बन रही हैं वैसी लोगों को अपेक्षा नहीं थी जो उनके सोशल मीडिया विचारों से समझा जा सकता है।

कमीशन का खेल है, अपनी जेब भरने, नेता, अधिकारी, पक्ष, विपक्ष मौन हैं, आरोप : सड़क बनते ही उखड़ जाने के मामले में लोगों का आरोप है कि ऐसा केवल अपनी जेब भरने के लिए किया जा रहा है और

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

शहर में हाल ही में बन रही सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्यों के बाद लोगों ने फेसबुक पर अनेक टिप्पणियाँ करते हुए निर्माण की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री एवं विभागीय लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए, नागरिकों का आरोप है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों में ही उसकी स्थिति खराब दिखने लगी है, जिससे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं, सबसे पहले एक यूजर ने सवाल उठाया कि टायरिंग के दौरान किस इंजीनियर की ड्यूटी थी और कार्य की निगरानी किसने की। कई लोगों ने सड़क निर्माण स्थल की पहचान स्पेस टेक्नोलॉजी रोड क्षेत्र के रूप में की और दावा किया कि निर्माण के दौरान मानकों का पालन नहीं किया गया।

बता दे कि अंबिकापुर में सड़क निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और एक ओर शहर की खस्ताहाल सड़कें अब बनाई जा रही हैं वहीं यदि सोशल मीडिया की पोस्ट देखी जाए तो बन रही सड़कें बनते ही उखड़ जा रही हैं और वह पुनः अपने खस्ताहाल स्थिति में पहुंच जा रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं और लोगों का एक तरह का ही बयान देखने को मिल रहा है जिसमें वह इसे भ्रष्टाचार की हद बता रहे हैं, इन सब के बीच सड़क लगातार बन भी रही है और उखड़ भी जा रही है, अंबिकापुर में सड़कों की खस्ताहालत को लेकर पिछले कुछ महीनों से नगर निगम सहित क्षेत्रीय विधायक सांसद को भी काफी कुछ आलोचना सहना पड़ चुकी है और आलोचनाओं के बाद और खरी-खोटी सुनने के बाद ही उन्होंने सड़क निर्माण कार्य का निर्णय लेते हुए नगर निगम से सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर कार्य का शुभारंभ कराया था लेकिन जिन सड़कों को बनाया जा रहा है उसकी हालत देखकर लगता है कि सड़कें केवल कमीशन प्राप्ति और अपनी जेब भरने के लिए बनाई जा

गुलाब कॉलोनी में शासकीय आवासों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू, 15 दिन में खाली करने का आदेश

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

गुलाब कॉलोनी में शासकीय आवासों को तोड़ने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। राजस्व अमले की मौजूदगी में तीन खाली शासकीय मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। गुलाब कॉलोनी में कुल 13 शासकीय मकान हैं, जिनमें से तीन पूरी तरह से खाली हैं। इन मकानों को तोड़ने का काम जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। गुलाब कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और हाल ही में दीपावली के समय इन आवासों का रंग-रोगन और मरम्मत का काम किया था। अब अचानक मकान खाली करने के लिए दिए गए समय को वे पर्याप्त नहीं मानते। इन कर्मचारियों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने और रोजगार के कामों के बीच किराए के मकान को खोज करना उनके लिए कठिन हो गया है। राजस्व अमले के अनुसार, गुलाब



कॉलोनी का निर्माण 1982-83 में हुआ था और तब से कई शासकीय कर्मचारियों, जिनमें न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं, को इन आवासों का लाभ मिला है। हालांकि, कॉलोनी के पास नजुल भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिया था। इनमें से कुछ लोग उच्च न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त कर चुके हैं और उनका मामला अभी अदालत में लंबित है। इस बीच, गुलाब कॉलोनी के नए न्यायालय भवन के निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया था। कलेक्टर ने शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर चट्टिमरा में भूमि आवंटित की थी, लेकिन अधिवक्ताओं का मानना था कि

भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्शों पर आधारित है: पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने गत दिवस देर शाम को पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक संस्कृति है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सार्वभौमिक आदर्शों पर आधारित है। यह संस्कृति केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और समाज को जोड़ने का विज्ञान है। उन्होंने अपने तीखे और प्रभावशाली अंदाज में कहा कि आज सनातन परंपरा पर योजनावद्ध प्रहार किए जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं, वे भारत की आत्मा को तोड़ना चाहते हैं। जो राम को नकारते हैं, वे भारत के अस्तित्व को नकारते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि भारत का युवा आज तकनीक से संपन्न है, लेकिन उसे अपनी जड़ों से जुड़ा रहना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति क्या है - और हमें अपने ज्ञान का



उपयोग 'देश के निर्माण' में करना है, न कि 'संस्कृति के विनाश' में। श्री कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद सत्ता या भूगोल से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना से उत्पन्न होता है। जब तक यह चेतना जीवित है, तब तक भारत अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत में धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं, बल्कि कर्तव्य और मर्यादा है। हमारे ग्रंथों ने कभी किसी पर वर्चस्व की भावना नहीं रखी-उन्होंने पूरे विश्व के

कल्याण की कामना की। अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि आज कुछ शक्तियाँ भारतीय संस्कृति को पिछड़ा बताने का षडयंत्र कर रही हैं, जबकि सत्य यह है कि भारत की संस्कृति ही विश्व को दिशा देने वाली है। जो भारत को समझना चाहता है, उसे भारत के ऋषियों, वेदों और परंपराओं को समझना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि

सरगुजा में पहली बार आयोजित होगी राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता, प्रदेशभर के 400 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन सरगुजा एवं नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में सरगुजा जिले में पहली बार राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 15 से 16 नवंबर तक माउंट लिट्टा स्कूल, संजयनगर में आयोजित होगी। इस राज्य स्तरीय आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं, जो अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा जिले में नेटबॉल का यह पहला बड़ा आयोजन होने का यह है। इस आयोजन से जिले में खेल के प्रति नई ऊर्जा, उत्साह और जागरूकता का संचार होगा तथा आने वाले समय में सरगुजा से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। पूर्व में भी सरगुजा जिले से कई खिलाड़ी नेट बॉल में मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किए हैं इस प्रकार के प्रतियोगिता से यहां की प्रतिभा और निखरकर सामने आएगी।

जनजातियों के हक के लिए बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी प्रेरणादायक : सांसद

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जनजातीय जिला सरगुजा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंबिकापुर इकाई द्वारा माता राजमोहिनी सभागार में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 'हम बिरसा हम गौरव' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरगुजा लोकसभा के सांसद चिंतामणी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। परिषद के वक्ता पलाश पांडे और नगर मंत्री सत्येंद्र मिश्रा भी मंच पर मौजूद थे। सांसद चिंतामणी महाराज ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि बिना किसी संचार माध्यम के, सिर्फ अपनी आत्मीय शक्ति से उन्होंने जनजातीय समाज को एकजुट किया और अंग्रेजों से संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन जनजातियों के हक के लिए उनका संघर्ष



आज भी प्रेरणादायक है। वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के नायक के रूप में प्रस्तुत किया। परिषद के वक्ता पलाश पांडे ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाती है और उनके आदर्शों को

अपनाती है। नगर मंत्री सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को आत्मसात करते हुए हमें समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न महाविद्यालयों, छात्रावासों और संस्थानों के विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में जनजातीय छात्र उपस्थित रहे।

डॉ. आर.एस. सिंह बने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव

—संवाददाता—
सूरजपुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जिले के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक डॉ. आर.एस. सिंह को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी संघ का प्रांतीय महासचिव नियुक्त किया गया है। उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति को आधिकारिक घोषणा होते ही स्वास्थ्य अमले में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभागीय कर्मचारियों ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव और मजबूत

नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। डॉ. सिंह पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनकी गिनती अनुभवी, संवेदनशील और परिणाम-उन्मुख चिकित्सकों में होती है। सूरजपुर जिले में पदस्थापना के दौरान उन्होंने नया-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और जनजागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के समय उनकी रणनीतियों और नेतृत्व में महती भूमिका निभाई थी।

सील बट्टा मारकर पत्नी ने की थी हत्या,सूटकेस हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा

-संवाददाता-
जशपुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जिले में 9 नवंबर को सूटकेस में मिले शव मामले को पुलिस ने खुलासा किया है। इस घण्ट्य वारदात को अंजाम देने वाली मृतक की पत्नी मंगरीता भगत (40 वर्ष) को पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड जंक्शन से गिरफ्तार किया है। पूरा मामला दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है। जानकारी के अनुसार, 9 नवंबर को ग्राम भिंजपुर स्थित घर में संतोष भगत की लाश एक सूटकेस में मिली थी। इस मामले में मृतक के भाई विनोद भगत की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी मंगरीता भगत को ही हत्या का आरोपी पाया, जो घटना के बाद फरार हो गई थी। शशि मोहन सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर और तकनीकी जांच के आधार पर पता चला कि आरोपिया पूर्व में मुंबई में काम करती थी और फरारी के दौरान महाराष्ट्र भाग गई है। पुलिस टीम ने जीआरपी एसपी श्वेता सिन्हा, डीएसपी अख्तर और आरपीएफ पुलिस की मदद से मनमाड रेलवे स्टेशन से मंगरीता भगत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपिया ने बताया कि उसके और पति के बीच चरित्र संबंधी विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी इसी बात पर बहस के दौरान उसने घर में रखे सील बट्टे (पीसने की पाटी) से पति के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर घर में ही छिपा दिया और दूसरे दिन फरार हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सील बट्टे को बरामद कर लिया है। आरोपिया ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पति की हत्या कर फरार हुई आरोपिया पत्नी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने जीआरपी रायपुर व आरपीएफ के सहयोग से इस मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है।



फर्जी डीएसपी बनकर नौकरी लगवाने के नाम पर बहतर लाख रुपए लेने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

-संवाददाता-
कुसमी, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के कुसमी पुलिस ने जे सी बी ऑपरेंटर से फर्जी डी एस पी बनकर पीड़िता से नौकरी लगवाने के नाम से बहतर हजार रुपए ठगी कर लम्बे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 92/2025, धारा 318(2), 319(2), 336(3), 340 बी. एन.एस. कार्यवाही कर आरोपी संतोष कुमार पटेल पिता रविनाथ पटेल उम्र 29 वर्ष सा0 पड़खुरी पंचोखर थाना चुरहट जिला सीधी मध्यप्रदेश को भेजा सलाखों के पीछे। जानकारी के अनुसार आरोपी ने प्राथीया को अपने विश्वास में लेकर अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर, पीड़िता के बच्चों को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 7200000/- (बहतर लाख रुपये) की ठगी फर्जी डीएसपी बताकर आरोपी संतोष कुमार पटेल के द्वारा की गई थी, आरोपी ए साई कंपनी में ऑपरेंटर के पद पर कार्य करता था ,



आरोपी संतोष कुमार पटेल, पिता रविनाथ पटेल उम्र 29 वर्ष सा0 पड़खुरी पंचोखर थाना चुरहट जिला सीधी मध्यप्रदेश जो वर्ष 2016 में ए. साई कंपनी के द्वारा सामरी, जलजली एवं श्रीकोट के पेटी में रोड निर्माण का काम लिया था, जिसका रोड निर्माण का काम चल रहा था। ए.साई कंपनी में आरोपी जे.सी.बी. ऑपरेंटर का काम करता था। वर्ष 2016-2017 में

नंबर 9302084236 ललकी बाई को दिया था और ललकी बाई का मोबाइल नंबर-6260528735 में बातचीत करता था। प्राथीया ललकी बाई से बात करते करते अपने विश्वास में बातचीत करते रहता था। सामरी, जलजली एवं श्रीकोट रोड निर्माण कार्य के दौरान सन् 2016 से 2021 तक आरोपी संतोष कुमार पटेल जे. सी. बी. ऑपरेंटर का काम किया। उसके बाद अपने घर ग्राम पड़खुरी चला गया। घर जाने के बाद आरोपी ललकी बाई को बोला कि मेरा म.प्र. पुलिस में डी.एस.पी का नौकरी लग गया है। तुम्हारा दोनो बच्चों का पुलिस में अच्छे पद पर नौकरी लगा दूंगा पर पैसा लोगा। मेरा भी पैसा देकर नौकरी लगवाया हूँ। झूठ बोलकर आरोपी के द्वारा प्राथीया ललकी बाई को अपने यूनिवर्सिटी के खाता क्रमांक 396202010055766 में उसके खाता नंबर से एवं आरोपी के संतोष कुमार पटेल अपने मोबाइल नंबर 9302084236 में फोन पे के माध्यम से वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक विभिन्न किस्तों में झूठ बोलकर ललकी बाई के

बच्चों को नौकरी लगवाने एव पत्नी का तबियत, कभी बहन का तबियत खराब है बोलकर रुपये पैसे की मांग कर कुल 7200000/- रुपये की ठगी किया गया है। मामले में थाना कुसमी को शिकायत प्राप्त होने पर थाना कुसमी में धारा 318(2), 319(2), 336(3), 340 बी. एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर विवेचना कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी इम्मानुएल लकडा अनुभाग कुसमी के कुशल मार्गदर्शन में थाना कुसमी से टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतु मध्यप्रदेश रवाना किया गया। टैबिकल जांचकारी के आधार पर आरोपी संतोष कुमार पटेल पिता रविनाथ पटेल उम्र 29 वर्ष सा0 पड़खुरी पंचोखर थाना चुरहट जिला सीधी मध्यप्रदेश को हिरासत में लेकर पृच्छाछ करने द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में 'यूथ डायलॉग सीरीज' के अंतर्गत प्रेरणादायक सत्र का आयोजन

भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट ऋषभ गुप्ता ने विद्यार्थियों से करियर, अनुशासन और आत्मविकास पर की बातचीत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में 'यूथ डायलॉग सीरीज' के अंतर्गत एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के सोशल इन्वोक्शन एंड कम्युनिटी एंजमेंट सेल और मुहिम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट ऋषभ गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए अपने जीवन के अनुशासन, समर्पण और संघर्ष के अनुभव साझा किए तथा युवाओं को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को करियर योजना, परीक्षा की तैयारी और व्यक्तिगत



विकास से संबंधित व्यावहारिक सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इंटरनेट और एआई टूल्स का रचनात्मक उपयोग करें, नए अवसरों की खोज करें और एक-दूसरे से सीखने की संस्कृति विकसित करें। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे साथियों का चयन करने, टीमवर्क को बढ़ावा देने और सीखने की मानसिकता बनाए रखने की भी सलाह दी।

लेफ्टिनेंट ऋषभ गुप्ता सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के मूल निवासी हैं एवं वर्तमान में भारतीय नौसेना में मुंबई में पदस्थ हैं। वे सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पूर्व छात्र हैं। उनकी उपस्थिति से विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र से एक युवा अधिकारी से संवाद और प्रेरणा लेने का एक विशेष अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 'एकता पदयात्रा' का आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी सरगुजा द्वारा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के अवसर पर भव्य 'एकता पदयात्रा' का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक पदयात्रा सांसद चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिंसोदिया की उपस्थिति में अम्बिकापुर से परसा तक निकाली गई। पदयात्रा का शुभारंभ राम मंदिर प्रांगण, अम्बिकापुर से हुआ, जहां भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र-छात्राई और बड़ी संख्या में आमजन श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित हुए। यात्रा मल्टीपरपज स्कूल मैदान से होकर शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहाँ शिव के दर्शन करने के बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया। मार्ग में शासकीय माध्यमिक शाला असोला में आमसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित



किए गए। सांसद चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल न केवल एक राजनेता थे, बल्कि उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपूर्व योगदान दिया। उन्होंने भारत की 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए कठिन संघर्ष किया, चाहे वह जुनागढ़, हैदराबाद या जम्मू-कश्मीर हो। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिंसोदिया ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन त्याग और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक था। उन्होंने गांधीजी के सिद्धांतों को अपनाने पर प्रशंसक बोलते हुए कहा कि मजबूत किया।

लायंस क्लब द्वारा बृहद निःशुल्क डायबिटीज परीक्षण शिविर

-संवाददाता-
क्या आपको डायबिटीज और बढ़ने लगा है शर्कर लेवल?



अम्बिकापुर, 13 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर लायंस क्लब अम्बिकापुर सरगुजा एव एस.आर.एस. हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14 नवम्बर को निःशुल्क बृहद डायबिटीज परीक्षण, परामर्श का आयोजन एस. आर. एस. हॉस्पिटल में हॉस्पिटल रोड अम्बिकापुर में सुबह 10 बजे से किया गया है। अधिक से अधिक लोग शिविर का लाभ उठाने हेतु क्लब द्वारा निवेदन किया गया है।

स्वर्णकार वेल्फेयर एसोसिएशन, स्वर्णकार समाज एवं सराफा एसोसिएशन ने सरगुजा आईजी को किया सम्मानित

राजेश ज्वेलर्स रामानुजगंज में हुए लूट कांड में डकैतों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में बलरामपुर पुलिस की कार्यवाही की सराहना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

राजेश ज्वेलर्स रामानुजगंज में विगत वर्ष 2024 सितंबर में दिन दहाड़े हुई सबसे बड़ी डकैती के आरोपियों को रामानुजगंज और बलरामपुर पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के द्वारा तत्परता से सभी डकैती के आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं डकैती किए गए समान की जप्त कर न्यायालय में तत्काल चलाया पेश कर न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही में तत्परता दिखाते हुए लगभग 14 माह में न्यायालय द्वारा



सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में रामानुजगंज, बलरामपुर पुलिस और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, सरगुजा आईजी महोदय का सम्पूर्ण सहयोग रहा और तत्परता से सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया उक्त डकैती कांड में तत्काल मिले न्याय से समस्त स्वर्णकार समाज में अत्यंत हर्ष का

माहौल है, इसी तत्वाधान में स्वर्णकार वेल्फेयर छत्तीसगढ़, सरगुजा स्वर्णकार समाज, एवं सराफा एसोसिएशन सरगुजा के पदाधिकारियों के द्वारा सरगुजा के

राजपुर बीच सड़क में रोड बनने को लेकर नगरवासियों ने सांसद, कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
राजपुर, 13 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत एनएच 343 बीच सेंटर से सड़क बनाने की मांग को लेकर नगरवासियों ने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, बलरामपुर कलेक्टर, सरगुजा एनएच 343 के कार्यपालन अभियंता के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नगरवासियों ने ज्ञापन में बताया है कि राजपुर नगर पंचायत एनएच 343 सड़क निर्माण को बीच सेंटर से बनाया जाए। जिससे नगर पंचायत के व्यापारी अपना अपना व्यापार कर सकें। नगरवासियों के द्वारा दिए गए आवेदन में बताया है कि नगर पंचायत सड़क के कुछ स्थानों पर एनएच 343 के द्वारा



चुना से एक साइड मार्किंग कर दिए हैं जिसके कारण बहुत से व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। समस्याओं को देखते हुए व्यापारियों ने दिया आवेदन, नगर के व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए नगर पंचायत में सड़क निर्माण बीच सेंटर से बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह, अनिल सोनी, मखन लाल अग्रवाल, दीपक मिश्र, विकास बंसल, छोट्टे गुप्ता, राहुल बंसल,

सतीश अग्रवाल, रजत केशरी, बंटी अग्रवाल, अजय अग्रवाल, मुकेश कुमार, विशाल अग्रवाल, अहमद राजा, अनूप पैकार आदि शामिल रहे। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा कि एसडीएम और एनएच वाले को बोला हूँ सड़क बीच सेंटर से बनाने को। पृष्ठे पर एसडीएम देवेन्द्र कुमार प्रधान ने नगरवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि एनएच से बात कर नगर में सड़क बीच सेंटर से बनवाया जाएगा।

मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी सात फीसदी 2026 में 6.5 फीसदी रहने का जताया अनुमान

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग ने गुरुवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) 2025 में सात फीसदी और अगले वर्ष 6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। भारत के लिए वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित होती है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपने 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक' में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक अनुमान जताए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की विकास दर 2025 में 7 फीसदी और 2026 में 6.5 फीसदी रहने की संभावना है। मूडीज रेटिंग ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत बुनियादी ढांचे पर खर्च एवं ठोस उपभोग से समर्थन मिल रहा है। हालांकि, निजी क्षेत्र व्यवसायिक पूंजीगत व्यय को लेकर सतर्क बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उम्मीद जताई है कि 2026 और 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 फीसदी के आसपास बढ़ती रहेगी, जिसे कम मुद्रास्फीति के बीच तटस्थ-से-उदार मौद्रिक नीति



रुख का समर्थन प्राप्त होगा। एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत जी-20 देशों के सदस्यों में से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह वर्ष 2027 तक 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगा जिसे घरेलू एवं निर्यात विविधीकरण का समर्थन प्राप्त मिलेगा। कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान है, जो 2024 के 6.7 फीसदी से अधिक है। मूडीज ने चीन के लिए अनुमान लगाया है कि 2025 उसकी में अर्थव्यवस्था पांच फीसदी बढ़ेगी। जिसे सरकारी प्रोत्साहन और मजबूत निर्यात का समर्थन प्राप्त होगा। 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि धीरे-धीरे घटकर 4.2 फीसदी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जीडीपी की वृद्धि दर 2026 और 2027 में 2.5 एवं 2.6 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है, जो 2025 के 2.6 फीसदी और 2024 के 2.9 फीसदी से कम है।

भारत-कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास मंत्री मनिंदर सिद्धू ने गुरुवार को नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर 7वें भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद (एमडीटीआई) की सह-अध्यक्षता की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच

व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए सिद्धू भारत में हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नए रोडमैप 2025 के हिस्से के रूप में व्यापार और निवेश पर 7वीं भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करना खुशी की बात थी। गोयल ने कहा कि कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और हमारे देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई।



अदाणी पोर्ट बना टीएनएफडी का सदस्य, प्रकृति आधारित रिपोर्टिंग शुरू करने का लिया संकल्प

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 2025। गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा स्थित अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) अब टास्कफोर्स ऑन नेचर-रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स (टीएनएफडी) की आधिकारिक सदस्य बन गई है। इस पहल के तहत कंपनी प्राकृतिक संसाधनों पर अपने प्रभाव, जोखिमों और अवसरों की रिपोर्ट टीएनएफडी फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार करेगी। इस प्रकार, एपीएसईजेड देश की ऐसी पहली इंटेंग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बन गई



है, जिसने पर्यावरण हितैषी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक नया मानक तय किया है। यह जानकारी एपीएसईजेड ने अपनी विज्ञापित में दी। इसमें बताया गया कि टीएनएफडी एक वैश्विक और विज्ञान-केन्द्रित पहल है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (यूएनडीपी एफआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

(यूएनडीपी), वर्ल्ड वाइडलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) और स्थायित्व कैनेपी जैसी संस्थाओं ने साथ मिलकर शुरू किया है। इसका उद्देश्य कंपनियों को यह समझाने में मदद करना है कि वे प्रकृति से जुड़े जोखिमों, प्रभावों और अवसरों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन कैसे करें। एपीएसईजेड अब उन चुनिंदा वैश्विक पोर्ट ऑपरेटर्स की सूची में शामिल हो गया है, जो जैव विविधता को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम

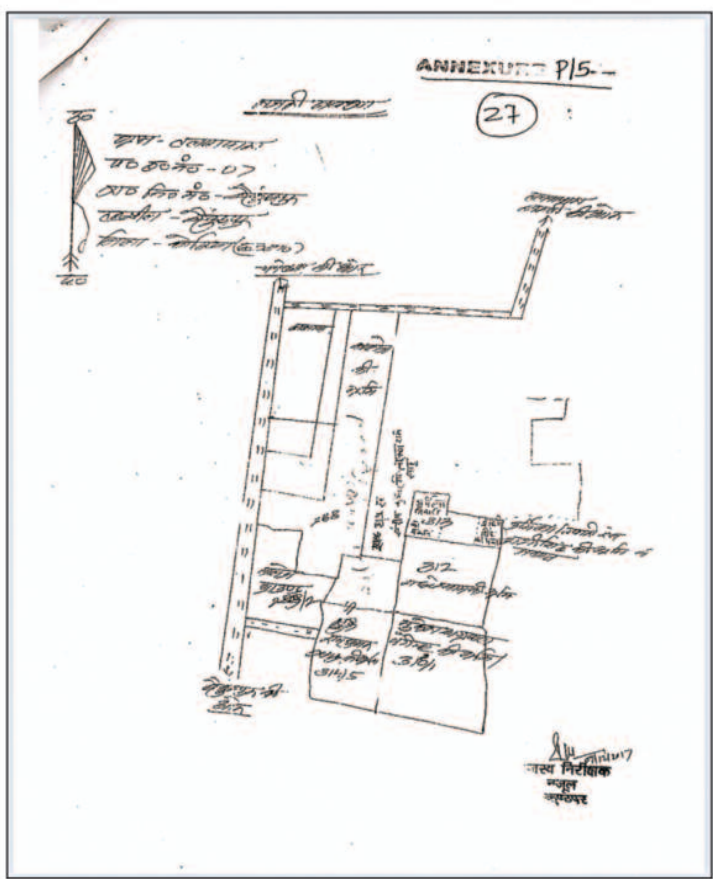
एपीएसईजेड के प्रकृति-समर्थक व्यावसायिक दृष्टिकोण को और मजबूत बनाता है और इसे टिकाऊ समुद्री लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित करता है। इस अवसर पर एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी गुप्ता ने कहा, हम दृढ़ता से मानते हैं कि जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएँ ही दीर्घकालिक सफलता की नींव हैं। टीएनएफडी फ्रेमवर्क को अपनाना, कॉप-30 में प्रकृति से जुड़ी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के प्रति हमारे समर्थन को दर्शाता है।



जमीन महाविद्यालय की चिंता किसी और की...?

जिन्हें लड़ना था, वे देखते रहे, जिन्हें लड़ना नहीं था, वे अदालत पहुँचे...

महाविद्यालय की जमीन पर निर्माण और जिम्मेदारों की चुप्पी... हाईकोर्ट ने कॉलेज भूमि विवाद पर जनहित याचिका खारिज की, सुरक्षा राशि भी जब्त...



महाविद्यालय के इतिहास में छिपा सच—यह जमीन पहले से ही महाविद्यालय को देने की प्रक्रिया में थी...

05 सितंबर 1982: महाविद्यालय की स्थापना

1986-87 महाविद्यालय के नाम पर भूमि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू

1995-99 महाविद्यालय का संचालन इन भवनों में जारी

पुराने भवन की कई बार मरम्मत महाविद्यालय निधि से

यह भवन महाविद्यालय की परिसंपत्ति के रूप में उपयोग में आता रहा तो फिर ऐसी जमीन को आज एसपी ऑफिस बनाने के लिए कैसे दे दिया गया ?

तया प्रशासन की मजबूरी थी या जिद?

छात्र संगठनों (एबीवीपी सहित) ने विरोध किया

महाविद्यालय प्रबंधन ने आपत्ति दी

विपक्ष ने मुद्दा उठाया

सामाजिक संगठनों ने भी कहा कि यह गलत है

यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय सांसद ने भी आपत्ति की फिर भी जिला प्रशासन... फैसला नहीं बदलेगा के रुख पर अड़ा रहा, तो तया यह जिद थी या मजबूरी ?

-रवि सिंह-
कोरिया, 13 नवंबर 2025
(घटती-घटना)।
जमीन थोड़ी थी पर भविष्य बड़ा था...मगर

अब जिले में शिक्षा जगत और समाज के बीच गंभीर चर्चा का विषय बन गया है, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव महाविद्यालय, जो पिछले 46 वर्षों से कोरिया जिले का अग्रणी उच्च शिक्षा केंद्र रहा है, आज अपनी ही भूमि के एक हिस्से पर दूसरे विभाग का निर्माण होते देख रहा है। यह वही भूमि है, जो आगे चलकर शिक्षा का हब बन सकती थी, लेकिन इसे पुलिस विभाग को आवंटित कर दिया गया वह भी कॉलेज से किसी तरह की स्पष्ट अनापत्ति के लिए बिना। कुछ दिनों तक विरोध हुआ, आवाज उठी, लेकिन समय के साथ विरोध शांत हो गया, जो विरोध करना चाहिए था,

कोई हित नहीं है। साथ ही जमानत राशि भी जब्त कर ली, महाविद्यालय परिसर से लगी वह जमीन, जिसे शिक्षा का हब बनाया जा सकता था, जिस पर नए विभाग, नई प्रयोगशालाएं, ऑडिटोरियम और विस्तार योजनाएं बन सकती थीं, उसे अब पुलिस विभाग को दे दिया गया है। और सबसे दुखद वह भी बिना महाविद्यालय से अनापत्ति लिए, निर्माण तेजी से शुरू हो चुका है, कुछ दिनों तक छात्रों के हित में, शिक्षा के भविष्य को रक्षा के लिए अदालत पहुंची, लेकिन न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें आपका

यहाँ सबसे कड़वा सच यही है...

जिस महाविद्यालय को अपनी जमीन बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, वह पूरे प्रकरण में मूक दर्शक बना रहा, हजारों छात्रों वाला यह महाविद्यालय चुप क्यों रहा? क्या जिम्मेदारों को अपनी ही जमीन की जानकारी नहीं थी? या फिर उनके ऊपर किसी का दबाव था? या फिर उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि भविष्य में छात्रों के लिए सुविधा बचेगी या नहीं। राजनीति के लिए मुद्दा मिल गया, विरोध को मंच मिल गया, बैठकों को बहस मिल गई पर महाविद्यालय को नहीं मिला, अपनी जमीन बचाने का साहस। और अंत में, एक संस्था जो सच में छात्रों के भविष्य की चिंता कर रही थी, वह अदालत गई, लेकिन हित के नाम पर रोक दी गई।

तया राजस्व विभाग को 2017 का नजरी नक्शा नहीं दिखा ?

खसरा नंबर 288 पर महाविद्यालय स्थापित होने के दस्तावेज सामने आए, फिर उसी जमीन को एसपी ऑफिस के लिए कैसे दे दिया गया? प्रशासन की जिद, प्राचार्य की चुप्पी और महाविद्यालय की जमीन पर तेजी से बढ़ता कब्जाज्जवालों के घेरे में पूरा तंत्र कोरिया जिले का चर्चित महाविद्यालय भूमि विवाद अब और भी उलझ गया है। जहां जिला प्रशासन यह दावा करता रहा है कि खसरा नंबर 288 महाविद्यालय की जमीन नहीं है, वहीं दैनिक घटती-घटना के हाथ 2017 का आधिकारिक नजरी नक्शा लगा है, जिसमें साफ-साफ दर्ज है खसरा नंबर 288 महाविद्यालय भवन खसरा नंबर 289 महाविद्यालय का खेल मैदान यानी 2017 में राजस्व विभाग स्वयं यह मान चुका था कि यह भूमि महाविद्यालय की है, तो फिर सवाल बड़ा है 2017 में महाविद्यालय की जमीन, 2025 आते-आते एसपी ऑफिस की जमीन कैसे बन गई?

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, कहा यह जनहित नहीं

छतीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने डब्ल्यू.पी.पी.आई.एल 91/2025 को खारिज करते हुए कहा कि- यह याचिका जनहित प्रतीत नहीं होती याचिकाकर्ता इस मामले में अधिकृत पक्ष नहीं हैं स्वयं कॉलेज ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की, विभागीय प्रक्रियाएँ और एनओसी लेकर ही 0.500 हेक्टेयर भूमि पुलिस विभाग को दी गई इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए पीआईएल के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं की जमा सुरक्षा राशि जब्त करने का आदेश दिया। क्या यह मामला जनहित नहीं था? सबसे बड़ा सवाल, अगर शिक्षा और छात्रों का भविष्य जनहित नहीं, तो फिर क्या है? हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अधिकृत पक्ष नहीं हैं कॉलेज स्वयं याचिकाकर्ता नहीं है इसलिए यह जनहित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत याचिका प्रतीत होती है।

तया राजस्व विभाग नौसिखियों के भरोसे चल रहा है ?

जमीन के रिकॉर्ड, नजरी नक्शे, कब्जे की वास्तविक स्थिति, स्कूल-कॉलेज का अस्तित्व सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या नौसिखिए राजस्व अधिकारियों ने बिना जमीन देखे ही आवंटन आदेश बना दिया? या फिर जानबूझकर ही महाविद्यालय की मौजूदगी को आदेश से छुपाया गया? जो भी हो, यह मामला नियमों, प्रक्रिया और प्रशासन की पारदर्शिता पर गंभीर पदा डालता है।

महाविद्यालय की जमीन पर निर्माण, प्राचार्य और प्रबंधन गहरी नींद में ?

जहां जमीन बचाने में महाविद्यालय की सबसे ज्यादा रुचि होनी चाहिए थी, वहीं प्राचार्य और प्रबंधन पूरी तरह मौन हैं, 46 साल पुराने महाविद्यालय की जमीन की सीमा कहा है, क्या प्राचार्य को भी नहीं पता? महाविद्यालय की जमीन पर कक्षा भवन, खेल मैदान, पेड़बूझो, पुरानी बिल्डिंग, सब मौजूद है, फिर भी कोई आपत्ति क्यों नहीं आई?

याचिकाकर्ताओं का दावा, कॉलेज की भूमि की जमीन छीनी गई

कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े और उपाध्यक्ष जयचंद्र सोनपाकर ने आरोप लगाया था महाविद्यालय की अलैटिड भूमि में से 0.500 हेक्टेयर जमीन को 31 जुलाई 2025 को कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण हेतु पुनः आवंटित कर दिया गया, यह भूमि कॉलेज विस्तार योजना और भविष्य की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन अदालत ने इन्हें अधिकृत पक्ष न मानते हुए कहा कि कॉलेज की ओर से किसी भी चरण में आपत्ति नहीं आई।

सरकार का पक्ष, अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में है...

राज्य सरकार की ओर से बताया गया जमीन सरकारी भूमि है, कॉलेज को केवल प्रस्तावित आवंटन था उसके राजस्व रिकॉर्ड और अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी एसपी ऑफिस बनाने हेतु जमीन विभागीय एनओसी के बाद विधिवत दी गई इससे कॉलेज के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

सबसे बड़ा सवाल: महाविद्यालय क्यों चुप रहा ?

यह विवाद अब एक बड़े और कड़वे सवाल पर आकर अटक गया है जब जमीन महाविद्यालय की थी, जब दस्तावेज और तथ्य कॉलेज के पास थे, जब भविष्य की शिक्षा और विस्तार का प्रश्न था तो महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या जिम्मेदारों पर कोई दबाव था? क्या उन्हें अपनी जमीन से अधिक अपना पद सुरक्षित रखना था? या फिर -उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इसलिए वे चुप बैठे रहे? पूर्व और वर्तमान दोनों ही प्रबंधन अब आलोचनाओं के घेरे में हैं क्योंकि 26 वर्षों तक महाविद्यालय से जुड़े अधिकारी भी इस जमीन को बचाने में निष्क्रिय दर्शक माने जा रहे हैं।

महाविद्यालय के भू-भाग पर और भी कब्जे, प्रबंधन मौन

दैनिक घटती-घटना की ग्राउंड जांच में सामने आय, महाविद्यालय की जमीन पर गैर-शासकीय निर्माण कुछ हिस्सों पर स्थायी कब्जे एक बड़े हिस्से पर धार्मिक पंडाल का निर्माण कार्य जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही धार्मिक उद्देश्यों से सरकारी भूमि के उपयोग को गैरकानूनी मानते हैं पर यहां प्राचार्य मौन, डीईओ मौन, जिला प्रशासन मौन क्या यह मौन अनुमति से कम है?

निष्कर्ष...

2017 के नक्शे ने खेल बिगाड़ दिया है... अब जब 2017 का नजरी नक्शा सामने है, तो यह स्पष्ट है... महाविद्यालय 288 और 289 पर ही है यह तथ्य प्रशासन से छिपाया नहीं जा सकता आवंटन आदेश में महाविद्यालय की मौजूदगी का उल्लेख न होना संदेह पैदा करता है प्रशासन की जिद, प्राचार्य की चुप्पी और जनप्रतिनिधियों की मौन स्वीकृति इन सबके बीच सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा और छात्रों का हो रहा है।

अब स्थिति...

पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण तेज गति से जारी है, समाज सेवी संस्था जिसने पीआईएल दायर की थी, अब निराश होकर पीछे हट चुकी है, और महाविद्यालय? अपनी ही भूमि पर निर्माण को चुपचाप होते हुए देख रहा है, आने वाले वर्षों में इस निर्णय का असर कॉलेज की विस्तार योजनाओं पर कितना पड़ेगा, यह समय बताएगा। लेकिन आज का सवाल-क्या सच में शिक्षा, जमीन से कम महत्वपूर्ण थी? जवाब अभी भी हवा में झूल रहा है।

घटती घटना | सुक्रवार 14 नवम्बर 2025

कौन कहता है कि खसरा नंबर 288 पर महाविद्यालय नहीं है, 2017 का नजरी नक्शा कहता है कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का ही है

तया छतीसगढ़ में राजस्व विभाग नौसिखियों के भरोसे चल रहा है ?

2017 में नजरी नक्शा जारी करने के बाद 2017 में महाविद्यालय का नजरी नक्शा सामने आया है, जो 2017 में महाविद्यालय की जमीन पर निर्माण के लिए आवंटित था, लेकिन नजरी नक्शा में 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

यह विवाद 2017 में शुरू हुआ था, तब जिला प्रशासन ने दावा किया कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें जिला प्रशासन ने दावा किया कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें जिला प्रशासन ने दावा किया कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

घटती घटना | सुक्रवार 14 नवम्बर 2025

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव शासकीय महाविद्यालय आखिर किस खसरा नंबर की भूमि पर है स्थापित ?

तया प्रशासन को पुलिस कार्यालय को जमीन आवंटित करते समय आवंटित की जा रही जमीन का सीमांकन करवाया ?

जिस जमीन पर शासकीय महाविद्यालय स्थापित है, उसकी सीमाएं और खसरा नंबर का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया गया है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें जिला प्रशासन ने दावा किया कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें जिला प्रशासन ने दावा किया कि 288 खसरा नंबर महाविद्यालय का नहीं है, बल्कि 289 खसरा नंबर महाविद्यालय का है।

**अंत में यह दो सवा...
तया संस्था अपने निजी लाभ के लिए गई थी ?
या फिर महाविद्यालय की जमीन और आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा बचाने के लिए ?**

सीमांकन हो जाए, तो कई चेहरे बेनकाब होंगे...

स्थानीय सूत्रों का दावा है यदि एक बार सीमांकन करा दिया जाए, तो महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने वालों की लंबी सूची सामने आ जाएगी। तो क्या यही वजह है कि प्रशासन सीमांकन कराने से बच रहा है?

सबसे बड़ा सवाल, जनप्रतिनिधि चुप क्यों ?

सभी जानते हैं महाविद्यालय की जमीन कम हो जाएगी भविष्य में कक्षाओं, ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाओं की जरूरत पड़ेगी, एसपी ऑफिस महाविद्यालय परिसर में बना तो छात्रों की स्वतंत्रता बाधित होगी फिर भी जनप्रतिनिधि चुप हैं, क्यों?

क्या महालेखाकार कार्यालय में भी बढ़ रही है अनियमितता की गंध?

अनियमितता की गंध?

वित्तीय अनियमितता की शिकायत लंबित, फिर भी सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य का जीपीएफ फंड किया गया भुगतान, सवाल के घेरे में प्रक्रिया

वित्तीय अनियमितता की शिकायत लंबित, फिर भी जीपीएफ भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण, जांच व्यवस्था पर उठे सवाल

अग्रणी महाविद्यालय की वित्तीय पारदर्शिता पर उठे सवाल, छह वर्षों से ऑडिट लंबित, जीपीएफ भुगतान प्रक्रिया पर भी संदेह

सूचना के अधिकार से खुलासा: कैशबुक अधूरी, ऑडिट रिपोर्ट अनुपलब्ध, फिर भी जीपीएफ भुगतान की प्रक्रिया आरंभ, जांच की मांग तेज

सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य के मामले में जांच में विलंब से बढ़ा विवाद, उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्न



-रवि सिंह-

रायपुर/कोरिया, 13 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में सरकारी लेखा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं, कोरिया जिले के एक शासकीय महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत लंबित रहने के बावजूद संबंधित अधिकारी को जीपीएफ (भविष्य निधि) राशि जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस निर्णय ने महालेखाकार कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, शिकायतकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजे जाने के बावजूद जांच की गति बेहद धीमी है। विभागीय स्तर पर स्पष्ट रिपोर्ट न आने से अब महालेखाकार कार्यालय की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं।

बता दे की कोरिया जिला मुख्यालय स्थित शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव अग्रणी महाविद्यालय बैकुण्ठपुर में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में यह सामने आया है कि विगत छह वर्षों से महाविद्यालय की कैशबुक का ऑडिट नहीं हुआ, और कई स्थानों पर एंट्री अधूरी है, हस्ताक्षर गायब हैं, तथा संख्यात्मक विसंगतियाँ पाई गई थी पर आज तक शिकायत के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई।



शिकायत अभी जांच के अधीन, फिर भी भुगतान आदेश क्यों?

सूत्रों के अनुसार, संबंधित महाविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रभारी अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता और दस्तावेजों के दुरुपयोग की शिकायत लंबित है, जिसकी जांच उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से की जानी है। परंतु जांच पूरी हुए बिना ही महालेखाकार कार्यालय से उनके जीपीएफ भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ वित्तीय जांच लंबित है, तो नियमों के अनुसार जीपीएफ या पेंशन भुगतान रोकना आवश्यक होता है, जब तक कि जांच रिपोर्ट स्पष्ट न हो जाए।

महालेखाकार कार्यालय की भूमिका पर उठे सवाल

महालेखाकार कार्यालय भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है और इसका उद्देश्य ही सरकारी वित्तीय अनुशासन की निगरानी करना है, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विभाग के पास संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत दर्ज है, तो बिना जांच पूर्ण हुए भुगतान का आदेश क्यों? वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसी प्रक्रिया बिना जांच के पूरी की जाती है, तो यह वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और गलत उदाहरण स्थापित करती है।

ऑडिट रिपोर्ट छह वर्षों से लंबित-

दस्तावेजों के अनुसार, 2019 के बाद से महाविद्यालय की कैशबुक का ऑडिट नहीं हुआ है, कैशबुक में बैंक व ट्रेजरी टोटल भी नहीं है, जिससे आय-व्यय का संतुलन स्पष्ट नहीं हो पा रहा, कई पत्रों में हस्ताक्षर अनुपस्थित हैं और कुछ प्रविष्टियाँ वर्षों बाद दर्ज की गई हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वित्तीय अनियमितता का संकेत हो सकता है और इसकी जांच आवश्यक है।

सेवानिवृत्ति के बाद कैश बुक पूरी करने की कोशिश

सेवानिवृत्ति के छह महीने बाद पूर्व प्रभारी प्राचार्य द्वारा कैश बुक का टोटल और ऑडिट करवाने के लिए अनुमति मांगे जाने की सूचना ने और सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है, वर्षों बाद कैश बुक को पुनः संशोधित या टोटल करने का प्रयास, प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करता है।

जीपीएफ भुगतान प्रक्रिया पर भी संदेह

सामाजिक संगठनों और कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि ऑडिट और जांच लंबित हैं, तो किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्ति भुगतान, विशेषकर जीपीएफ (भविष्य निधि) तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक जांच पूरी न हो जाए। जानकारों के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के 4 जुलाई 2025 के संशोधित आदेश के तहत, ऐसे मामलों में भुगतान तब तक स्थगित रहेगा जब तक वित्तीय अनियमितता से जुड़ी जांच पूरी न हो जाए। एक शिक्षाविद ने कहा - यदि जांच पूरी होने से पहले भुगतान कर दिया जाता है, तो यह विभागीय नियमों की अवहेलना होगी और भविष्य में जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाएगा।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों की मांग

भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शारदा प्रसाद गुप्ता ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, और कलेक्टर कोरिया को पत्र भेजा था, पत्र में पिछले 15 वर्षों के वित्तीय दस्तावेजों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में राजनीतिक खींचतान और प्रभार विवाद के चलते प्रशासनिक व वित्तीय अनुशासन प्रभावित हुआ है।

जनता की मांग, स्वतंत्र जांच हो...

स्थानीय शिक्षकों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि शासन को इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच समिति गठित कर कैशबुक, ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय लेनदेन का भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए, जनता का कहना है कि जब महाविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्था में पारदर्शिता पर प्रश्न उठने लगे, तो यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक विफलता का भी संकेत है।

जनता और प्रशासनिक हलकों में चर्चा...

इस पूरे मामले ने स्थानीय प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। कई कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या महालेखाकार कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में भी अब प्रभाव और पहुँच के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं? जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि यदि वित्तीय अनुशासन की निगरानी करने वाला ही विभाग नियमों की अनदेखी करेगा, तो जवाबदेही की उम्मीद कहाँ से की जाएगी।

पारदर्शी जांच की मांग...

स्थानीय स्तर पर अब इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है, सामाजिक संगठनों और कर्मचारी संघों का कहना है कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच लंबित मामलों में किसी प्रकार का भुगतान न हो, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार या प्रभावशाली हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे।

जांच लंबित होने पर भी भुगतान, क्या यह नियमों के विपरीत है?

वित्तीय नियमों के अनुसार यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता या भ्रष्टाचार की जांच लंबित हो, तो उसकी सेवा से जुड़ी वित्तीय देनदारियों (जैसे जीपीएफ, ग्रेच्युटी या पेंशन) का भुगतान जांच पूर्ण होने तक रोकना जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में, जांच लंबित रहते हुए भुगतान आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आने से वित्तीय अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

जनता की मांग, पारदर्शी जांच और जवाबदेही

जनता और स्थानीय नागरिक संगठनों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग को इस मामले में जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि महालेखाकार और शिक्षा विभाग दोनों की विश्वसनीयता बनी रहे, यदि जांच लंबित रहते हुए भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो यह वित्तीय प्रशासनिक जवाबदेही पर गहरा प्रश्नचिह्न छोड़ जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने मांगी स्पष्ट

कर्मचारी संगठनों और शिक्षाविदों ने इस पूरे प्रकरण में जांच की पारदर्शिता और समय सीमा तय करने की मांग की है, उनका कहना है कि यदि जांच लंबी खींचती रही और बीच में भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए गलत परंपरा स्थापित हो सकती है। एक शिक्षा कर्मी ने कहा जांच अधूरी रहते हुए भुगतान होना यह संकेत देता है कि प्रशासनिक नियमों की गंभीरता कम हो रही है। जांच पूरी होने तक किसी भी आर्थिक भुगतान पर रोक लगनी चाहिए।

विभागीय सूत्रों की प्रतिक्रिया-

विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को भेजी गई है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया है, सूत्रों के अनुसार, जांच में देरी का कारण दस्तावेजों की पुष्टि और वित्तीय अभिलेखों की जटिलता बताई जा रही है।

जांच में विलंब से बढ़ रहा अविश्वास

कई सामाजिक संगठनों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या जांच को जानबूझकर विलंबित किया जा रहा है ताकि संबंधित व्यक्ति को अपने पक्ष में राहत मिल सके, सूत्रों के अनुसार, आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में वित्तीय अनियमितता की कुछ बातें सामने आई हैं, जिनकी जांच होना आवश्यक है।

प्रमुख विसंगतियाँ (आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार)

2019 के बाद से ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं...

कई वर्षों के बैंक व ट्रेजरी टोटल अनुपस्थित...

कई पत्रों पर हस्ताक्षर गायब...

कटिंग और सुधार बिना सत्यापन हस्ताक्षर के...

सेवानिवृत्ति के बाद भी कैश बुक अधूरी...

जनभागीदारी एवं पी.डी. खाते का लेखा असंतुलित...



पूर्व में प्रकाशित की गई खबरों की कतरनें

Advertisement for 'Ghatati Ghana' newspaper, featuring the masthead, date (November 25, 2025), and a main headline: 'शासकीय महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य वित्तीय अनियमितता फैलने के बाद भी कैसे निश्चित हैं...की उन पर कार्यवाही नहीं होगी और ना ही जांच होगी?'.

शराब घोटाला... चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के खिलाफ ईडी का एक्शन, 364 प्लॉट अटैच

रायपुर, 13 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, अटैच की गई संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं। जिनकी कीमत 59.96 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त की गई हैं। शराब घोटाला मामले में अब तक कुल 276 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। वहीं कांग्रेस ने इसे विद्रोहपूर्ण कार्रवाई बताया है। संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पैतृक संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी।



चैतन्य बघेल सिंडिकेट का प्रमुख था...

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि चैतन्य बघेल सिंडिकेट के सर्वोच्च स्तर पर था। उसकी स्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण वही पूरे नेटवर्क का नियंत्रक और फैसले लेने वाला व्यक्ति था। सिंडिकेट द्वारा इकट्ठा की गई अवैध रकम का हिस्सा वही रखता था। कलेक्शन, चैनलाइजेशन और वितरण से जुड़े सभी प्रमुख फैसले उसके डायरेक्शन पर लिए जाते थे।

अटैच कमाई को 'विटल ग्रीन' में लगाया गया

ईडी ने बताया कि चैतन्य ने शराब घोटाले से कमाई की गई रकम को अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगाया और उसे वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की। उसने यह पैसा अपनी फर्म एम.एस. बघेल डेवलपर्स के तहत संचालित प्रोजेक्ट 'विटल ग्रीन' में लगाया। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ में मारे गये 27 लाख के इनामी छह नक्सलियों की हुई शिनाख्त

बीजापुर, 13 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र के कांदुलनार, कचलारम और गुज्जाकोटा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच 11 नवंबर को हुई मुठभेड़ में 27 लाख रुपये के इनामी तीन महिला सहित छह नक्सली मारे गए थे। मारे गये सभी नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ स्थल से दो इन्सास रायफल, 05 मैगजीन, 68 कारतूस, एक 9 एमएम काबाइन, 03 मैगजीन, 22 कारतूस, तीन .303 रायफल, एक मैगजीन 13 कारतूस, एक सिगल शॉट रायफल, एक 12 बोर बंदूक, 08 कारतूस, रेडियो, स्के नर, मल्टीमीटर, हेण्डग्रेनेड, सेफ्टीफ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मैडिकल सामग्री एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस संयुक्त अभियान को डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दत्तेवाड़ा और एसटीएफ की टीमों ने अंजाम दिया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने गुरुवार को बीजापुर में आयोजित प्रेसकारवाता में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षाबलों को डीकेएसजेडीसीएम पापावर, महेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज डीवीसीएम कन्ना उर्फ बुचन्ना, डीवीसीएम उर्मिला, डीवीसीएम मोहन कड़ती सहित पश्चिम बस्तर डिवीजन के करीब 50 से 60 नक्सलियों के एक बड़े समूह को मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने तत्काल इलाके में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। 11 नवंबर की सुबह लगभग 10 बजे से शुरू हुई यह मुठभेड़ रक-रक कर दो दिनों तक जारी रही, जिसमें अंततः छह प्रमुख नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली। डीवीसीएम कन्ना उर्फ बुचन्ना : यह 8 लाख रुपये के इनामी महेड़ एरिया कमेटी का प्रभारी था और गुड्डेपाल, थाना मोदकपाल का निवासी था। पिछले एक दशक से अधिक समय से पुलिस और आम नागरिकों पर हुए कई हमलों का यह मास्टरमाइंड था। उसके खिलाफ 42 आपराधिक मामले दर्ज थे और 18 स्थायी वारंट जारी थे। पुलिस को मिले दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि उसका शहरी नेटवर्क से भी गहरा जुड़ाव था। डीवीसीएम उर्मिला पति पापावर : यह 8 लाख रुपये के इनामी चितलनार, जिला सुकमा की निवासी थी और प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता पापावर की पत्नी थी। वह पापेड़ एरिया कमेटी की सचिव के तौर पर काम कर रही थी और पीएलजीए बटालियन की रसद व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती थी। उसकी मौत से पापेड़ एरिया कमेटी और पीएलजीए बटालियन की सलाई चैन को बड़ा झटका लगा है। बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में बीजापुर जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 144 नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान में 499 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 560 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाये गये अभियान में कुल 202 नक्सली मारे गये, 1002 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 749 नक्सलियों ने हिंसा का रस्ता छोड़कर समाज की मुखाधारा में शामिल हुए।



नक्सल विरोधी अभियान

शराब घोटाले में 2500 करोड़ की अटैच कमाई...

ईडी ने यह जांच एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं लगाई गई थीं। जांच में पता चला कि इस घोटाले से राज्य सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का खेल चला।

जिला अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही... आयुक्त ने देर रात गठित की 3 सदस्यीय जांच समिति..



बीजापुर, 13 नवम्बर 2025। बीजापुर जिला अस्पताल में हुए नेत्र ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों में देखने में समस्या का सामना करना पड़ा। इस मामले ने अब स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त (स्वास्थ्य सेवाएं) सह-संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने देर रात 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है।

जांच समिति में शामिल अधिकारी

डॉ. निधि अग्रवाल- राज्य कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. महेश साडिया- संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बस्तर संभाग और डॉ. सरिता थॉमस- नेत्र शल्य चिकित्सक, जिला अस्पताल जगदलपुर की समिति को 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह समिति नेत्र शल्य चिकित्सा के दौरान आई जटिलताओं के कारणों की विस्तृत जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय सुझाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही आयुक्त डॉ. शुक्ला ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 मरीजों को रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराने के निर्देश दिए। सभी मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां और उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए गए हैं।

रात 11:45 बजे गठित हुई जांच टीम

डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि उन्हें देर शाम लगभग 8-9 बजे घटना की जानकारी मिली थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने देर रात 11:45 बजे जांच टीम का गठन किया। मरीजों के बेहतर उपचार की व्यवस्था प्राथमिकता पर रखी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सूचना आयुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मुहर, 25 साल अनुभव की शर्त को दी वैधता



बिलासपुर, 13 नवम्बर 2025। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का फैसला कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सचं कमेटी द्वारा तय 25 साल के अनुभव की शर्त न तो मनमाना है और न ही अवैध। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि जब किसी पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, तब शॉर्टलिस्टिंग चयन प्रक्रिया का स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा होता है। दरअसल, अनिल तिवारी, राजेंद्र कुमार पाठक और डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुभव की शर्त जोड़ना 'खेल के बीच नियम बदलने' जैसा है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15(5) और 15(6) में अनुभव की कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं की गई है। उनका कहना था कि 25 साल की अनिवार्यता विधिक प्रावधानों के खिलाफ है। हालांकि, सचं कमेटी ने 9 मई 2025 को तय किया था कि केवल वही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य होंगे, जिनके पास विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन या शासन के क्षेत्र में कम से कम 25 साल का अनुभव हो और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो। राज्य सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि सचं कमेटी का यह निर्णय आरटीआई अधिनियम के अनुरूप है। अधिनियम में सूचना आयुक्त के लिए 'व्यापक ज्ञान और अनुभव' को आवश्यक बताया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सचं कमेटी को योग्यता और अनुभव के मापदंड तय करने का पूरा अधिकार है।

छत्तीसगढ़ पुलिस का अद्भुत रिकॉर्ड! 9 साल पुराना मामला 24 घंटे में खत्म, लापरवाही के लिए 6 एसआई, डीएसपी दंडित...

रायपुर, 13 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद राज्य पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने अम्बिकापुर के एक 9 साल पुराने आपराधिक मामले की जांच में हुई देरी पर सख्त कदम उठाया है। डीजीपी ने खुद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया, जिसके 24 घंटे के भीतर ही साक्ष्य के अभाव में केस को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस विभाग ने लापरवाही के लिए 6 उपनिरीक्षकों (एसआई) की 1 वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी है, जबकि तत्कालीन डीएसपी मणीशंकर चंद्रा के खिलाफ 'निराशा' का दंड लगाया गया है।



लखनलाल वर्मा के खिलाफ अम्बिकापुर में धारा 384, 502, 504, 34 धाद्विक के तहत अपराध दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनके 2 सह-आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जानबूझकर जांच को लंबित रखे हुए है। 6 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने

डीएसपी ने लॉबी रिपोर्ट, 7 अफसरों पर हुई कार्रवाई...

डीएसपी अरुण देव गौतम ने अदालत को बताया कि आदेश मिलते ही पुलिस मुख्यालय ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। देरी के लिए जिम्मेदार अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने ने 6 उपनिरीक्षक- नरेश चौहान, विनय सिंह, मनीष सिंह परिहार, प्रियेश जॉन, नरेश साहू और वंश नारायण शर्मा की 1 वर्ष की अस्थायी वेतन वृद्धि रोक दी गई। वहीं तत्कालीन डीएसपी मणीशंकर चंद्रा को 'निराशा का दंड' दिया गया है।

कोर्ट में डीएसपी का हलफनामा... हलफनामे में डीएसपी ने कहा कि जांच के दौरान कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए मामले में अब धारा 169 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट विचारण न्यायालय में पेश की जा रही है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया गया है।

बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर फिर मचा बवाल रायपुर में गौवंश तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, 13 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार रात सरकंडा थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में उस समय हंगामा मच गया जब हिंदू संगठनों को सूचना मिली कि एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर की शाम को एसईसीएल में पदस्थ झड़वर राजेंद्र खरे ने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की थी। बताया जा रहा है कि इस सभा में बहतराई और खमतराई क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बुलाया गया था। सभा में कुल 20 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें करीब 7 से 8



बच्चे भी मौजूद थे। हिंदू संगठनों के सदस्यों का आरोप है कि इस सभा में उपस्थित लोगों को हिंदू धर्म के प्रति भ्रामक बातें बताकर ईसाई धर्म अपना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यहाँ तक कि सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें कही जा रही थीं। कार्यकर्ताओं के अनुसार, राजेंद्र खरे लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और लोगों को धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था।

रायपुर में गौवंश तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 13 नवम्बर 2025। राजधानी रायपुर में गौवंश तस्करी के खिलाफ खमतराई पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो inter-state गौ तस्करी गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं, तीसरा मुख्य आरोपी विवेक तिवारी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उमेश दावड़ (36 वर्ष), निवासी टेका नगर, नागपुर (महाराष्ट्र) और विकास तिवारी (21 वर्ष), निवासी अमरपाटन, जिला सतना (मध्यप्रदेश) शामिल हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, दिनांक 01 नवंबर 2025 को सुबह सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडी 9815 में भारी मात्रा में गौवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर थाना खमतराई पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर मेटल पार्क, रांवाभाठा, धरनेली नाला क्षेत्र में नाकेबंदी की। सुबह करीब 4 बजे उक्त ट्रक मौके पर आया, लेकिन पुलिस को देखकर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, तो कुल 24 नग गौवंश (नंदी) ट्रक में भरे मिले, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने प्रार्थी प्रिंस सिंह परमार (26 वर्ष), निवासी कैलाश नगर, बीरगांव की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1164/25 दर्ज किया।

रायपुर में रिम्स हॉस्पिटल ने शव को बनाया बंधक, थानों के चक्कर लगा रहा मृतक का पिता



रायपुर, 13 नवम्बर 2025। रिम्स हॉस्पिटल पर लड़की की लाश को बंधक बनाने का आरोप लगा है। पूरा मामला मंदिर हसींद थाना क्षेत्र का है, जहाँ रिम्स हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जानकारी के मुताबिक राजिम निवासी किसान की बेटी का शव नहीं देने पर हंगामा खड़ा हो गया है, सांप के काटने पर 07 नवंबर को रिम्स में भर्ती कराया गया था, 15 साल की बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन

धान बेचने के लिए अब एप से मिलेगा टोकन... खाद्य विभाग ने लॉन्च किया 'तुहर टोकन' ऐप, 70% धान खरीदी ऑनलाइन जारी टोकन से होगी

रायपुर, 13 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में इस बार मोबाइल एप के जरिए ही किसान धान बेचने के लिए टोकन ले पाएंगे। इसके लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए नया मोबाइल एप 'तुहर टोकन' लॉन्च किया है। सबसे अच्छे स्मार्टफोन इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को पहले आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। हर दिन सुबह 8 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए किसान खरीदी के लिए टोकन बना सकेंगे। सीमांत किसान को 1 एकड़, लघु को 2 और दीर्घ को 3 टोकन तक की सुविधा है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए किसानों की श्रेणी के अनुसार टोकन की संख्या तय की गई है -

सकेगा। जारी टोकन अगले 7 खरीदी दिवसों के लिए मान्य रहेंगे। मोबाइल एप से 70% खरीदी, लघु-सीमांत किसानों को 80% आरक्षण : धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन की सीमा में से 70% खरीदी मोबाइल एप टोकन के माध्यम से होगी। इस 70% में से 80% लघु और सीमांत किसानों के लिए और 20% दीर्घ किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है, तो मोबाइल एप के माध्यम से 700 क्विंटल खरीदी होगी। इसमें 560 क्विंटल लघु और सीमांत किसानों और 140 क्विंटल दीर्घ किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। शेष 30% टोकन समितियों (सोसाइटी) में उपलब्ध रहेंगे ताकि सभी वर्ग के किसान धान विक्रय के लिए आवेदन कर सकें/खाद्य विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था समान अवसर, पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित करेगी।